



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38 ]  
No. 38]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2000/चैत्र 24, 1922  
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2000/CHAITRA 24, 1922

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2000

सं. टीएएमपी/1/97-एच.डी.सी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार 2 दिसम्बर, 1999 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में अधिसूचित हल्दिया स्थित कलकत्ता पत्तन न्यास की भूमि और भवनों के लिए किराए की दरों को संशोधित करता है।

अनुसूची

मामला सं. ० टीएएमपी/1/97-एचडीसी

कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी)

..... आवेदक

आदेश

(मार्च, 2000 के 27वें दिन को पारित किया गया)

इस प्राधिकरण ने 29 अक्तूबर, 99 को मामला सं. ० टीएएमपी/1/97-एचडीसी में हल्दिया स्थित कलकत्ता पत्तन—न्यास के भवनों और भूमि की दरों के संशोधन से संबंधित एक आदेश पारित किया था।

यह आदेश राजपत्र सं0 103 के द्वारा दिनांक 2 दिसम्बर, 1999 को भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग—III, खंड—4) में अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त आदेश के अनुबंध—1 के पैराग्राफ 1.2 के शीर्षक में मुद्रण संबंधी त्रुटि है। असाधारणीवश 'प्रति' वर्गमीटर के स्थान पर '100' वर्गमीटर संख्या दी गई थी। इसलिए, उक्त आदेश के अनुबंध—1 के पैराग्राफ 1.2 को हटाया जाता है और निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"किराए/लाइसेंस शुल्क की दर प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह"

3. कलकत्ता पत्तन न्यास सीपीटी ने 29 अक्टूबर, 99 के उक्त आदेश में कई संशोधन करने का सुझाव दिया है। सीपीटी ने हमारे द्वारा पहले अनुमोदित "पोत—प्रति—पोत के आधार पर" आबंटन के स्थान पर 1 वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न आयातकों/निर्यातकों को कार्गो के पारगमन भंडारण के लिए डॉक आंतरिक क्षेत्र में भूमि आबंटन का प्रस्ताव किया है। यह परिवर्तन प्रयोक्ताओं के साथ विस्तृत विचार—विमर्श के पश्चात पत्तन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। पता चला है कि प्रयोक्ता सीपीटी के इस प्रस्ताव से सहमत हैं।

4. सीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को प्राधिकरण ने अनुमोदित कर दिया है। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित करता है:—

(i) आदेश के अनुबंध—1 में, भूमि और भवनों के लिए किराए की अनुसूची क्रम सं0 1 के अंतर्गत टिप्पणी (2) में 1.1 भूमि के संबंध में "पोत—प्रति—पोत के आधार पर" शब्दों को हटाया जाता है। टिप्पणी (2) के अंतर्गत उप—पैराग्राफ को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

टिप्पणी 2 " \*डॉक आंतरिक क्षेत्र के भीतर आयात/निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के भंडारण के लिए आबंटन के मामले में यह दरें लागू नहीं हैं।"

(ii) आदेश के अनुबंध—1 में क्रम सं0 1.2 भवनों के लिए, के अंतर्गत उप पैराग्राफ, मद (ट) "गुमटी" के बाद "पोत—प्रति—पोत के आधार पर" शब्दों को हटाया जाता है। उप—पैराग्राफ को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"\*डॉक आंतरिक क्षेत्र के भीतर आयात/निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के भंडारण के लिए आबंटन के मामले में यह दरें लागू नहीं हैं।"

(iii) आदेश के अनुबंध—1 के क्रम सं0 1.7 में "पोत—प्रति—पोत के आधार पर" शब्दों को हटाया जाता है। क्रम सं0 1.7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"आयात/निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के भंडारण लिए डॉक आंतरिक क्षेत्र के भीतर खुले/ढके हुए स्थान के लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क निम्नलिखित दरों पर भारित किया जाएगा। विस्तृत प्रक्रिया टिप्पणियों के खंड—17 में दी गई है।"

(iv) उक्त आदेश के अनुबंध—1 की टिप्पणियों के खंड—17 को हटाया जाता है और निम्नानुसार

” 17 आयात/निर्यात किए जाने वाले कार्गो के भंडारण के लिए डॉक के भीतरी क्षेत्र के अंदर खुले/ढके हुए स्थान का लाइसेंस निविदा प्रक्रिया अपनाए दिना एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक किराया आधार पर प्रदान किया जा सकता है। ऐसे मामलों में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए:—

- (i) अपनी वस्तुओं के भंडारण के लिए स्थान का आवंटन चाहने वाले पत्तन प्रयोक्ता महाप्रबंधक (प्रचालन) को आवेदन कर सकते हैं। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (एच) को ऐसे स्थान के आवंटन के लिए स्वीकृति देना अथवा मना करने का विवेकाधिकार होगा।
- (ii) लाइसेंस की अवधि एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
- (iii) आवंटित किया गया स्थान शिकमी पर/सुपुर्द/हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
- (iv) लाइसेंसधारक द्वारा भूमि और रेलमार्ग के अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे के कारण उसे पत्तन संपत्तियों को हुई क्षति के सुधार की लागत के अलावा अनुसूचित लाइसेंस शुल्क के 10 गुना दर पर जुर्माने का भुगतान करना होगा। नोटिस दिए जाने के बाद भी यदि लाइसेंसधारक अतिक्रमण किए गए क्षेत्र से कार्गो हटाने में असफल रहता है तो लाइसेंसधारक के जोखिम और लागत पर पत्तन द्वारा कार्गो किसी अन्य स्थान पर भेज दिया जाएगा और इस प्रकार हटाए गए कार्गो द्वारा धेरे गए स्थान के लिए सामान्य दर के दस गुना दर पर जुर्माना लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा।
- (v) लाइसेंस के अंतर्गत भंडार किया गया कार्गो पूर्णतया लाइसेंसधारक के जोखिम और उत्तरदायित्व पर होगा। लाइसेंसधारक उसे आवंटित स्थान पर भंडार किए गए कार्गो की सुरक्षा और अन्यों द्वारा ऐसे स्थान के अनाधिकार कब्जे को रोकने के लिए अपना चौकीदार तैनात करेगा।
- (vi) लाइसेंसधारक लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध स्थान पर कोई भवन, उत्थापन या सुविधा का निर्माण अथवा स्थापना नहीं करेगा।
- (vii) लाइसेंसधारक के लाइसेंस की तारीख समाप्त होने पर स्थान को खाली कब्जे में सुपुर्द करने में असफल रहने पर एच.डी.सी./सी.पी.टी. लाइसेंस प्रदान किए जाने की अवधि से आगे एच.डी.सी./सी.पी.टी. के परिसर में कार्गो के रखे रहने की अवधि के लिए समय—समय पर लागू एचडीसी/सीपीटी के दरों के मान के अनुसार सामान्य विलंब शुल्क प्रभार वसूल करेगा।
- (viii) यदि लाइसेंसधारक लाइसेंस का विस्तार चाहता है, तब विस्तार के लिए आवेदन किया जाए, जोकि महाप्रबंधक (प्रचालन) के पास लाइसेंस की अवधि के समाप्त होने के कम से कम 15 दिन पहले पहुंच जाए। स्वीकृत सभी अनुवर्ती विस्तारों सहित लाइसेंस की कुल अवधि, स्थान के प्रारंभिक आवंटन की तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ix) लाइसेंसधारक एचडीसी/सीपीटी द्वारा सामग्रीमय समय में जारी सभी नियमों और निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत होगा। यदि लाइसेंसधारक ऐसे नियमों अथवा निर्देशों का पालन करने में लापरवाही करता है तो एचडीसी/सीपीटी लाइसेंस को रद्द कर सकता है।

(x) लाइसेंस किसी भी पक्ष द्वारा 15 दिन के नोटिस पर समझ किया जा सकता है।

(xi) लाइसेंसधारक लाइसेंस के संबंध में एचडीसी/सीपीटी को वेय किसी भी प्रकार के तभी भुगतानों और खर्चों की समय—समय पर एचडीसी/सीपीटी की किराया अनुसूची में निर्धारित दरों पर वसूली के लिए सहमत होगा।

(xii) लाइसेंसधारक नगरपालिका प्राधिकारी अथवा विस्टोटक भिरीकाक, विस्टोटक सामग्री विभाग, भारत सरकार अथवा कार्गो के भंडारण से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा समय—समय पर जारी सभी नियमों अथवा विनियमों का प्रालन करेगा।

(xiii) लाइसेंसधारक अनुसूचित दर पर लाइसेंस शुल्क के भुगतान के अलावा नगरपालिका शुल्क, यदि आवश्यक और यथा लागू हो, का भुगतान करेगा।

(xiv) यदि विजली सीपीटी द्वारा प्रदान की जाती है, तब लाइसेंसधारक आपूर्ति की गई विजली के लिए वास्तविक प्रभारों, मीटर किराया और केबल की लागत का भुगतान करेगा।

(xv) लाइसेंसधारक सीपीटी के चोतों से आपूर्ति किए गए पानी की वास्तविक लागत के साथ—साथ मीटर किराया और पाइपलाइन जोड़ने के प्रभारों का भुगतान करेगा।

(xvi) अधिसूचित किराया अनुसूची की 'टिप्पणियों' की मद परं 9 के अनुसार जमानत राशि का भुगतान लाइसेंसधारक द्वारा किया जाएगा।

(xvii) लाइसेंस शुल्क सीमांकन पर वास्तविक क्षेत्र में भूमि का कब्जा हिए जाने की तारीख से वसूल किया जाएगा। जमानत राशि का निर्धारण सीमांकन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा।

(xviii) लाइसेंस शुल्क के भुगतान और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में समय—सीमा संबंधित अधिसूचित किराया अनुसूची की 'टिप्पणियों' की मद संख्या (13), (14) और (15) भी लागू होंगी।

(xix) लाइसेंस को रद्द करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति के बावे को स्थिकार नहीं किया जाएगा।

(xx) लाइसेंसधारक आर्थित भूमि का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग करेगा, जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है। सीपीटी की ओर से विशिष्ट नियमित अनुमति के बिना उपयोग के प्रयोजन में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xxi) लाइसेंसधारक सीपीटी की संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तथागि गति कोई नक्सान नहीं है तो लाइसेंसधारक सीपीटी की संतुष्टि पर

अपनी लागत और प्रबंध पर नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(xxii) लाइसेंसधारक उसे आबंटित भूमि और उसके आस-पास के स्थान को साफ-सुथरा तथा उचित स्वच्छ स्थिति में रखने के लिए स्वयं अपने प्रबंध करेगा।"

5. उपर्युक्त संशोधनों के मद्देनजर, उक्त आदेश का पैराग्राफ 17.1(iii) हटाया जाता है और पैराग्राफ सं 17.1 (iv) को पैराग्राफ क.सं. 17.1(iii) दी जाती है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष  
[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/2000]

### TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2000

No. TAMP/1/97-HDC.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amends the rates of rent for land and buildings of the Calcutta Port Trust at Haldia notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 on 2nd December 1999, as in the Order appended hereto.

#### SCHEDULE

#### Case No. TAMP/1/97-HDC

Calcutta Port Trust (CPT)

.....

Applicant

#### ORDER

(Passed on this 27th day of March 2000)

This Authority had passed an Order on 29 October 99 in case No.TAMP/1/97-HDC relating to revision of rates for Land and Buildings of the Calcutta Port Trust in Haldia. This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary ( Part III Section 4) on 2 December 99 vide Gazette No.103.

2. There is a typographical error in the heading of paragraph 1.2. of Annex – I to the said Order. The figure '100' sq. m. was inadvertently given instead of 'per' sq. m. The heading of the paragraph 1.2 of the Annex – I to the Order is, therefore, deleted and substituted as given below :

"Rate of rent/licence fee per sq. m. per month"

3. The Calcutta Port Trust (CPT) has suggested certain amendments to the said Order dated 29 October 99. The CPT has proposed to allot lands inside the Dock Interior Zone for transit storage of cargo to various importers / exporters for a period of 1 year instead of allotment "on ship-to-ship basis" as approved by us earlier. This change has been proposed by the Port after a detailed discussion with the users. The users are reported to have agreed with the proposal of the CPT.

4. The amendments proposed by the CPT are approved by the Authority. In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the following further amendments to the said Order :-

(i). In Annex – I of the Order, NOTE (2) under Sl. No. I Schedule of Rent for Land and Buildings, I.1. For Land, the words “on ship to ship basis” are deleted. Sub paragraph under NOTE (2) is substituted as given below :

**NOTE (2)** “ \* These rates are not applicable in case of allotment for storage of import/export goods inside the Dock Interior Zone”.

(ii). In Annex – I of the order sub paragraph under Sl. No.1.2. For Buildings, after Item (k) “Goomties” the words “on ship to ship basis” are deleted. The said sub paragraph is substituted as given below :

“ \* These rates are not applicable in case of allotment for storage of import/export goods in the Dock Interior Zone”.

(iii). In Sl. No.II.7 of Annex – I of the Order, the words “on ship to ship basis” are deleted. Sl. No. II.7 is substituted by the following :

“ For licensing of open/covered space inside Dock Interior Zone for storage of import/export goods, the licence fee will be charged at the following rates. The detailed procedure is furnished in Clause – 17 NOTES :-”

(iv). Clause 17 of the NOTES of the Annex – I of the Order is deleted and substituted as given below :

“17. The licensing of open/covered space inside the Dock Interior Zone for a period upto one year on monthly rent basis for storage of import/export cargo may be done without recourse to a tender procedure. The following conditions shall be followed in such cases:-

- (i). Port users requiring allotment of space for storage of their cargo may apply to General Manager (Ops.). The Chairman / Dy. Chairman(H) shall have the discretion to allot or refuse to allot such space.
- (ii). The period of licence shall not exceed one year.
- (iii). The space allotted shall not be sublet/assigned/ transferred.
- (iv). Encroachment or unauthorised occupation of land and Railway tracks, etc., by the licensee will involve a liability to pay a penalty at the rate of ten times the scheduled licence fee, in addition to the cost of rectification of damages caused to the Port properties. If the licensee fails to remove the cargo from the encroached area in spite of notice to do so, the cargo

will be removed elsewhere by the Port at the risk and cost of the licensee and penal licence fee at the rate of ten times the normal rate will be levied on the space occupied by the cargo so removed.

- (v). Cargo stored under a licence shall be at the entire risk and responsibility of the licensee. The licensee shall post his own watchman to safeguard the cargo stored at the allotted space and to prevent any unauthorised occupation of such space by others.
- (vi). The licensee shall not construct or put up any building, erection or convenience on space occupied under licence.
- (vii). In case the licensee fails to hand over the space in vacant possession on the date of expiry of the licence, HDC/CPT shall levy normal demurrage charges as per HDC/CPT's Scale of Rates as applicable from time to time for the period the cargo remains in HDC/CPT's premises beyond the period for which the licence was granted.
- (viii). - If the licensee requires extension of the licence, an application for extension must be made so as to reach the General Manager (Ops.), at least 15 days before the expiry of the period of the licence. The total period of licence including all subsequent extension granted shall not exceed 3 years from the date of initial allotment of space.
- (ix). The licensee shall agree to comply with all rules and directions issued by HDC/CPT from time to time. If the licensee neglects to comply with such rules or directions, HDC/CPT may terminate the licence.
- (x). The license is terminable on 15 days' notice on either side.
- (xi). The licensee shall agree that all payments and expenses of whatever sort due to HDC/CPT in respect of the licence be recovered at the rates prescribed in HDC/CPT's Rent Schedule from time to time.
- (xii). The licensee shall comply with all rules or regulations that may from time to time be issued by the Municipal Authority or the Inspector or Explosives, Department of Explosives, Government of India or whomsoever concerned in relation to storage of cargo.
- (xiii). In addition to payment of licence fee at the scheduled rate the licensee shall pay municipal tax, if required and as applicable.

- (xiv). The licensee shall pay electricity charges for energy supplied at actuals, meter rent and cabling cost, if electricity is provided by the CPT.
- (xv). The licensee shall pay the cost of water at actuals, supplied from the CPT sources alongwith meter rent and pipeline connection charges.
- (xvi). Security deposit as per item 9 of 'Notes' of the notified rent schedule shall be payable by the licensee.
- (xvii). The license fee will be charged from the date of handing over possession of the land on the actual area to be found on demarcation. The amount of security deposit will also be determined on the actual area as found on demarcation.
- (xviii). Items (13), (14) and (15) of 'Notes' of the notified Rent Schedule regarding time frame for payment of licence fee and other related issues shall also be applicable.
- (xix). No claim for any compensation whatsoever for revocation of the licence will be entertained.
- (xx). The licensee shall be required to utilise the allotted land for the purpose for which it is licensed. No change in purpose of utilisation will be allowed without specific written permission from the CPT.
- (xxi). The licensee will not cause any damage to CPT properties. If, however, any damage is caused, the licensee shall be liable to make good the damages at his own cost and arrangement to the satisfaction of the CPT.
- (xxii). The licensee shall have to make his own arrangements to keep the allotted land and its surroundings neat, clean and in proper sanitary condition."

5. In view of the above amendments, paragraph 17.1. (iii) of the Order is deleted and paragraph 17.1 (iv) is re-numbered as para 17.1. (iii).

S. SATHYAM, Chairman  
[Advt./III/IV/Exty./143/2000]